VPM CLASSES

NTA UGC NET

PUBLIC ADMINISTRATION

SOLVED SAMPLE PAPER

(Hindi Medium)

* DETAILED SOLUTIONS
* NEW SYLLABUS
* NEW PATTERN

9001894070

www.vpmclasses.com

UGC NET | **लोक प्रशासन** | **FMTP**

समय–2 घण्टे **(प्रश्नपत्र II)** **अधिकतम अंक : 200**

नोट : इस प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हैं। सारे प्रश्न करना अनिवार्य हैं।

1. प्रक्रिया आधारित संगठनों के कार्य विभाजन से हानि यह है कि –

(1) तकनीकी क्षमता विकसित नहीं होती है।

(2) उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो पाती।

(3) लोकतांत्रिक नियंत्रण स्वीकार कम होता है।

(4) उपर्युक्त सभी

2. ए. एटजियोनी द्वारा वर्णित संगठनों के प्रकार के क्रम में निम्नांकित पर विचार कीजिए।

(1) प्रपीड़क संगठन (2) उपयोगितावादी संगठन

(3) आदर्शात्मक संगठन (4) सत्तात्मक संगठन

सही कूट चुनिए –

(1) 1, 2, 4 (2) 2, 3, 4 (3) 1, 2, 3 (4) 1, 3, 4

3. निम्न में से नियामकीय अभिकरण है –

(1) गृह मंत्रालय (2) जल संसाधन मंत्रालय

(3) भारतीय निर्वाचन आयोग (4) व्यापार बोर्ड

4. **कथन (A)** : केन्द्रीकरण की आवश्यकता सुरक्षा तथा गुप्त पर कार्यों में बहुत होती है।

कारण (R) : विकेन्द्रीकरण आज एक सिद्धान्त नहीं बल्कि जीवनशैली बन चुका है।

(1) **कथन** (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) **कथन** (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

5. केन्द्रीयकृत गृहपातन सेवाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया था –

(1) हूवर आयोग द्वारा (2) ब्राउनलों समिति द्वारा

(3) रॉयल कमीशन द्वारा (4) टॉमलिन आयोग द्वारा

6. ''संगठनात्मक प्रभावशीलता'' से सम्बन्धित है ?

(1) 4P सिंद्धात (2) 3E सिंद्धात

(3) 7S मॉडल (4) POSDCORB मॉडल

7. ''आउटवर्ड प्रत्यायोजन'' कहा जाता है –

(1) संगठन के कार्य बाहरी निकाय या समिति को देना

(2) देश के कार्य विदेशों को सौंपना

(3) सरकार के कार्य ओ.एण्ड.एम. को देना

(4) उपर्युक्त सभी

8. सुमेलित कीजिए –

(अ) 3I संगठन	(1) लुइस.ए.एलन
(ब) उलझाने वाली विधि	(2) हैण्डी
(स) केओरडिक ऑर्गेनाइजेशन	(3) शेमरॉक
(द) तिपत्तियाँ संगठन	(4) डी हॉक

(1) अ–1, ब–2, स–3, द–4

(2) अ–2, ब–3, स–4, द–1

(3) अ–1, ब–3, स–1, द–4

(4) अ–2, ब–1, स–4, द–3

9. न्यूमैन ने समन्वय हेतु जिन पूर्व शर्तों का उल्लेख किया है वह है –

(1) सरलीकृत संगठन (2) पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय

(3) व्यावसायिक दक्षता (4) सामजंस्य पूर्ण कार्य व नीतियां

(1) 1, 2 (2) 2, 3, 4 (3) 3, 4, 1 (4) 1, 2, 4

VPM CLASSES

10. ग्रेकुनाज के नियंत्रण के क्षेत्र सम्बन्धी गणितीय फॉमूले को अनुभवयुक्त निरीक्षण पर व्यावहारिक नहीं मानने वाले विद्वान् हैं–

(1) हेमैन (2) साइमन (3) मिलेट (4) उरविक

11. उद्योगों में अनुपस्थितिवाद के प्रयोगों के पश्चात् मेयो ने निष्कर्ष दिया कि–

(1) औपचारिक संगठनों की रचना जटिल है

(2) युद्ध के कारण श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं

(3) अनौपचारिक संगठनों तथा सहज नेतृत्व का अभाव अनुपस्थिति का कारण है

(4) श्रमिकों की ज्यादा यूनियनें घातक हैं

12. "Emerging Synthesis in Public Administration" के लेखक है।

(1) डेविड ईस्टन (2) हेण्डरसन

(3) साइमन (4) क्रिस आर्गिरिस

13. ''प्रंबध में भविष्यवक्ता'' कहा जाता है–

(1) टेलर को (2) साइमन को

(3) केयोल को (4) कॉलेट को

14. सुमेलित कीजिए

(अ) पेशेवर प्रकृति	(1) वारनॉट
(ब) ब्यूरोपैथोलॉजी	(2) कार्लाइल
(स) व्यावसायिक मनः सन्ताप	(3) थॉम्पसन
(द) महाद्वीपीय उत्पात	(4) डेवी

(1) अ–1, ब–2, स–3, द–4

(2) अ–4, ब–1, स–3, द–2

(3) अ–1, ब–3, स–4, द–2

(4) अ–4, ब–3, स–2, द–1

VPM CLASSES

15. अभिप्रेरणा के वाई सिद्धांत के क्रम में कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है –

(1) रेन्सिस लिकर्ट – नियोजित सक्रिय मानव

(2) पीटर ड्रकर – उद्देश्यों द्वारा प्रबंध

(3) क्रिस आर्गिरिस – एकीकृत एवं स्वनियंत्रित प्रबंध

(4) हजबर्ग – कार्य समृद्धता

16. भारतीय राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार निम्नलिखित में किन–किन का सम्मिश्रण है?

1. पाकेट वीटो
2. एब्सोल्यूट वीटो
3. सस्पेंसिव वीटो
4. क्वालिफायड वीटो

(1) 2 और 3

(2) 1, 3 और 4

(3) 2, 3 और 4

(4) 1, 2 और 3

17. कॉस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2005 के माध्यम से ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर के स्थान पर चुने जाने वाले पदाधिकारी का नाम रखा गया है–

(1) लॉर्ड एक्सचेकर

(2) लॉर्ड प्रेसीडेण्ट

(3) लॉर्ड स्पीकर

(4) लॉर्ड जस्टिस

18. अमेरिकी मंत्रालय, विभाग तथा प्रशासनिक संगठनों की आन्तरिक संरचना विभक्त की हुई है–

(1) ब्यूरो, डिविजन, डेस्क तथा सेक्शन में

(2) ब्यूरो, सर्विसेज, सेक्शन तथा एजेन्सी में

(3) ब्यूरो, डिविजन, ऑफिस तथा सर्विसेज में

(4) ब्यूरो, सर्विसेज, डेस्क तथा यूनिट में

19. वर्तमान फ्रांस में कौनसा गणतंत्र प्रवर्तित है ?

(1) प्रथम (2) तृतीय (3) नवम (4) पंचम

20. ''दिल्ली सैटलमेण्ट'' का सम्बंध है–

(1) पाकिस्तान (2) बांग्लादेश (3) चीन (4) नेपाल

VPM CLASSES

21. विकासशील राष्ट्रों में विकास प्रशासन से संकीर्ण तात्पर्य है–

(1) प्रशासनिक विकास से (2) परियोजना प्रशासन से

(3) पंचायती राज से (4) ग्रामीण अभिकरणों से

22. ''Sustain'' से तात्पर्य है–

(1) परम्परागत प्रशासन (2) विकास प्रशासन

(3) प्रशासनिक विकास (4) धारित विकास

23. डेविड एप्टर ने विकास के सन्दर्भ में बाधक मूल्यों को क्या नाम दिया है?

(1) उपकरणात्मक (2) पूर्णताकारक

(3) उत्प्रेरक तत्व (4) उपर्युक्त सभी

24. विकास प्रशासन की प्रकृति से असंगत तत्व है–

(1) परिवर्तन अनुकूलिक (2) लचीलापन

(3) केन्द्रीयकरण (4) नियोजित प्रयास

25. कथन (A) : विकास प्रशासन सामाजिक तथा आर्थिक समरसता के लिए कार्य करता है।

कारण (R) : विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास को जन्म देता है।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

26. केन्द्रीय सचिवालय की आन्तरिक प्रशासनिक रचना के सन्दर्भ में सही युग्म कौनसा है?

(1) उच्च स्तरीय प्रबंध = मंत्री एवं उनका निजी सहायक

(2) मध्य स्तरीय प्रबंध = निदेशक एवं उप सचिव

(3) निम्न प्रबंध = वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक

(4) समस्तरीय प्रबंध = योजना आयोग का जिला आलोचना समिति से समन्वय

VPM CLASSES

27. 'डेस्क सिस्टम' के क्रम में असत्य कथन कौनसा है?

(1) वह परम्परा ब्रिटेन के 'व्हाईट हॉल' से ली गई है।

(2) वह सन् 1950 में कुछ मंत्रालयों तथा सन् 1973 से व्यापक रूप से प्रवर्तित है।

(3) अनुभाग अधिकारी या अपर सचिव प्रायः डेस्क अधिकारी का पद धारण करते हैं।

(4) इस प्रणाली में डेस्क अधिकारी सभी मामले सचिव तक निर्णय करने हेतु नोटिंग सहित भेजता है।

28. 'स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बंधी राष्ट्रीय नीति' का प्रतिपादक निकाय है?

(1) कपार्ट

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(4) योजना आयोग

29. सुमेलित कीजिए–

(A) जनसंख्या स्थिरता कोष	(1) 1950
(B) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	(2) 2007
(C) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	(3) 1952
(D) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	(4) 1961

कूट :

	a	b	c	d
(1)	1	2	3	4
(2)	4	3	2	1
(3)	2	3	4	1
(4)	2	1	4	3

VPM CLASSES

30. कथन (A) : कार्यविधि के सरकारी समाश्वासन के अनुसार मंत्रिमण्डल सचिव भारतीय लोकसेवकों के मध्य प्रथम स्थान पर स्थित है।

कारण (R) : भारत सरकार के सरकारी कामकाज की जानकारी रखने में वह प्रधानमंत्री को चक्षु एवं कर्ण प्रदान करता है।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

31. ''डी.पी.सी.'' से तात्पर्य है–

(1) प्रत्यक्ष पदोन्नति कार्ड

(2) विभागीय पदोन्नति समिति

(3) प्रत्यक्ष पदोन्नति समिति

(4) दोहरी पदोन्नति का स्थायी कार्ड

32. कथन (A) : अखिल भारतीय सेवाओं ने संविधान के संघवाद सिद्धांत तथा राज्यों की स्वायत्तता को भंग किया है।

कारण (R) : अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन होते हैं तथा राज्य सरकारें इन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाती हैं।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

VPM CLASSES

33. सुमेलित कीजिए–

(a) प्रशासनिका	(1) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
(b) इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक	(2) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेशन
(c) मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट	(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(d) कुरूक्षेत्र	(4) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

कूट :

	a	b	c	d
(1)	1	3	2	4
(2)	1	4	2	3
(3)	4	2	1	3
(4)	2	3	1	4

34. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रारूप के द्वारा नई आवेदन प्रणाली कब से प्रारंभ की गई–

(1) 2000 (2) 1978 (3) 1999 (4) 1985

35. ''भारतीय आर्थिक सेवा'' का गठन किया गया–

(1) 1961 (2) 1957 (3) 1971 (4) 1994

36. सुमेलित कीजिए–

(a) पूर्व अंकेक्षण	(1) धन की उपलब्धता तथा व्यय की वैधता की जानकारी
(b) पश्चात् अंकेक्षण	(2) आय–व्यय तथा लेखांकन जाँच
(c) प्रशासनिक अंकेक्षण	(3) तकनीकी, कार्मिक तथासंगठनात्मक प्रक्रिया जाँच
(d) वित्तीय अंकेक्षण	(4) लेखों का पोस्टमार्टम

VPM CLASSES

कूट :

	a	b	c	d
(1)	1	4	3	2
(2)	1	4	2	3
(3)	4	1	2	3
(4)	3	2	1	4

37. भारत में ''एकीकृत वित्तीय सलाहकार व्यवस्था'' प्रारंभ की गयी–

(1) 1979 (2) 1974 (3) 1985 (4) 1975

38. ''शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान'' स्थित है–

(1) हैदराबाद (2) बैंगलोर (3) नई दिल्ली (4) मुम्बई

39. निम्नलिखित विषयों में से किनसे सम्बंधित उपबंध किसी विधेयक को धन विधेयक समझे जाने के लिए अर्हता प्राप्त करवाते हैं?

1. भारत के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना
2. भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा
3. किसी कर का परिवर्तन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

(1) 1 और 2 (2) 2 और 3 (3) 1 और 3 (4) 1, 2 और 3

40. कथन (A) : लोक प्रशासन में प्रशासन तथा वित्त पृथक् हैं।

कारण (R) : कार्यपालिका को वित्तीय स्वीकृति विधायिका देती है।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

VPM CLASSES

41. कथन (A) : संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारें, राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

कारण (R) : राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को प्रतिवर्ष जो अनुदान दिया जाता है, उसका निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा ही किया जाता है।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

42. भारत के संविधान में 'जिला' शब्द किस अनुच्छेद में तथा किस सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है?

(1) अनुच्छेद–311, लोक सेवाओं के सन्दर्भ में

(2) अनुच्छेद–356, राष्ट्रपति के सन्दर्भ में

(3) अनुच्छेद–233, जिला न्यायाधीश के सन्दर्भ में

(4) अनुच्छेद–365, राजस्व एकत्रण के सन्दर्भ में

43. भारत के संदर्भ में ''छोटा नेपोलियन'' किसे कहा गया है?

(1) कौटिल्य को (2) योजना आयोग को

(3) जिला कलक्टर को (4) पटवारी को

44. निम्नलिखित में से कौन–से मुद्दे/मुद्दों पर 13वें वित्त आयोग द्वारा उसके विचारार्थ विषय के अनुसार कार्य किया जाएगा?

1. राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की संचित निधि के आवर्धन हेतु आवश्यक उपाय।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निधीयन द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय संसाधनों के आवर्धन हेतु आवश्यक उपाय।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

(1) केवल 1 (2) केवल 2

(3) 1 और 2 दोनों (4) न तो 1 और न ह 2

VPM CLASSES

45. भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन–कौन से कार्य निर्धारित किए गए हैं?

1. नगरीय निर्धनता उपशमन
2. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
3. चर्मशोधनशालाओं का विनियमन
4. नगरीय वानिकी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

(1) 1, 2 और 3 (2) 2, 3 और 4

(3) 1 और 4 (4) 1, 2, 3 और 4

46. ''परिकल्पना'' होती है–

(1) एक निश्चित समाधान (2) प्रभावित साक्ष्य

(3) अनुमानित समाधान (4) उपर्युक्त सभी

47. योजना तंत्र से सम्बंधित P.E.O. मुख्यतः किस प्रकार की शोध निष्पादित करता है–

(1) विशुद्ध शोध (2) वर्णनात्मक शोध

(3) व्यावहारिक शोध (4) मूल्यांकनात्मक शोध

48. प्रशासन की दृष्टि से उपयुक्त आधुनिक शोध प्रविधि है–

(1) Rating Scale (2) DAT (3) Interview (4) AP

49. $(SEM) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ में ''σ'' है।

(1) न्यादर्श का आकार (2) मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि

(3) जनसंख्या का प्रमाणिक विचलन (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. समाजशास्त्रीय शोध के सम्पादन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह है।

1. उपकरणों की प्रमाणिकता की समस्या
2. मापन की समस्या
3. प्रत्ययों व तथ्यों का स्पष्ट अभाव
4. भविष्य कथन की समस्या

कूट :

(1) 1, 2 (2) 2 (3) 4, 3 (4) 1, 2, 3, 4

VPM CLASSES

51. स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु उचित मापदण्ड हैं–

(1) उसमें मूलभूत वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं हो।

(2) बही खाते एवं लेखा रखने की समुचित प्रणाली हो।

(3) जनता कार्यों हेतु इच्छुक होनी चाहिए।

(4) समूह को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए।

52. निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का बाह्य कारक है–

1. नियोजन
2. आन्तरिक दबाव
3. औद्योगिकीकरण
4. समाज के आदर्शों व यथार्थ में संघर्ष

(1) केवल 1
(2) 2, 3
(3) केवल 4
(4) केवल 3

53. सुमेलित कीजिए–

सूची–I (संविधान में संशोधन)	सूची–II (विषय वस्तु)
(a) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन अधिनियम), 1991	(1) राज्यस्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
(b) संविधान (पचहत्तरवां संशोधन अधिनियम), 1994	(2) अरूणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
(c) संविधान (अस्सीवां संशोधन अधिनियम), 2000	(3) गांवों या अन्य स्थानीय स्तरो पर पंचायतों का संगठन
(d) संविधान (तिरासीवां संशोधन अधिनियम), 2000	(4) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना
	(5) दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना

VPM CLASSES

कूट :

	a	b	c	d
(1)	5	1	4	2
(2)	1	5	3	4
(3)	5	1	3	4
(4)	1	5	4	2

54. ''लोक नीति किसी राजनीति कार्यकर्त्ताओं के समूह द्वारा किए गए निर्णयों की माला है, जिसका सम्बंध लक्ष्यों के चयन व एक निश्चित स्थिति के भीतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाये जाने वाले साधनों से है। जहां सिद्धांत रूप में ऐसे निर्णयों को करने का अधिकार उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सत्ता के दायरे में है।''

यह परिभाषा किस विद्वान की है–

(1) थॉमस डाई
(2) विलियम जेनकिन्स
(3) लुथर गुलिक
(4) सेक्लर हड़सन

55. सुमेलित कीजिए–

(a) सारगत नीतियां	(1) पोषाहार सहायता
(b) वितरक नीतियां	(2) वित्तीय प्रबंध सहायता
(c) पूंजीकरण नीतियां	(3) शैक्षिक प्रबंध
(d) नियंत्रक नीतियां	(4) राज्य परिवहन निगम

कूट :

	a	b	c	d
(1)	1	2	3	4
(2)	4	3	2	1
(3)	3	2	1	4
(4)	3	1	2	4

VPM CLASSES

56. कथन (A) : योजना आयोग भारत के सम्पूर्ण आयोजना तंत्र का प्रमुख केन्द्रबिन्दू बन चुका है।

कारण (R) : यह एक सूत्र अभिकरण है।

(1) A व R दोनों सही है व R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A व R दोनों सही है, किंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।

(3) A सही व R गलत है।

(4) A गलत व R सही है।

57. ''..... के आधारभूत मूल्य रास्ते के जंगली फूलों की भांति नहीं लिखते वरन् वे गहन उपजाऊ विश्वासों में उपजते हैं जिनमें सभ्यता पोषित होती है।''

(1) सामाजिक कार्य (2) सामाजिक नीति

(3) सामाजिक कानून (4) सामाजिक नियोजन

58. ''अल्पावास गृह कार्यक्रम'' का सम्बंध है–

(1) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

(2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

(3) राज्य समाज कल्याण बोर्ड

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय

59. ''TRYFED'' का गठन किया गया–

(1) वर्ष 1990 (2) वर्ष 1975

(3) वर्ष 1978 (4) वर्ष 1987

60. देश में उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार को परामर्श देने का उत्तरदायित्व किस संस्था का है?

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2) भारतीय अध्यापक संघ

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (4) विद्यार्थी यूनियन

61. The Rehabitation Plantations limited की स्थापना किस वर्ष की गई ?

(1) 1970 (2) 1962 (3) 1975 (4) 1979

VPM CLASSES

62. निम्न में से किसने लोक निगमों को ''बीसवीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक नवीनता या मौलिकता'' की संज्ञा दी है ?

(1) हेन्सन (2) रॉबसन

(3) हरबर्ट मोरीसन (4) अर्नेस्ट डेविस

63. भारत सरकार द्वारा नवरत्न योजना प्रारंभ की गई–

(1) 1979 (2) 1989

(3) 1996 (4) 1997

64. ''भारतीय प्रतियोगिता आयोग'' का कार्य है।

1. प्रतियोगिता परामर्श, जनता के मध्य जागरूकता तथा प्रशिक्षण
2. प्रशिक्षण, संगोष्ठियां तथा कार्यशाला सहित क्षमतावर्धन
3. प्रशासन, स्थापना, बजट तथा लेखांकन से सम्बंधित क्रियाकलाप

कूट :

(1) 1, 2 (2) 2, 3

(3) 1, 2, 3 (4) केवल 3

65. कथन (A) : उदारीकरण तथा निजीकरण का काल लोक सेवा की भर्ती के वातावरण में परिवर्तन ला देगा।

कारण (R) : लोक सेवा में सेवा के संरक्षण की उपलब्धता उत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करती रहेगी।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

VPM CLASSES

66. नगरपालिकाओं से संबंधित 74वें (संशोधन) अधिनियम के उपबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?

1. दो लाख तक की आबादी वाले वार्डों के लिए वार्ड् समितियां हो।

2. राज्यपाल नगरपालिकाओं को करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

3. छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद हो।

4. बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 20 कार्य मदों का उल्लेख है।

(1) 1, 3 और 4 (2) 1, 2 और 4 (3) केवल 3 (4) 3 और 4

67. छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ?

(1) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा (2) रक्षा सचिव द्वारा

(3) राज्य के मुख्य सचिव द्वारा (4) भारत के राष्ट्रपति द्वारा

68. ''बम्बई प्रादेशिक आयोजन परिषद्'' की स्थापना की गई–

(1) 1966 (2) 1975 (3) 1967 (4) 1968

69. पंचायती राज सशक्तिकरण हेतु केन्द्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए 3 f स्तर में शामिल नहीं है।

(1) फंक्शन (2) फण्ड (3) फंक्शनरीज (4) फोर्स

70. सुमेलित कीजिए–

(a) अनु. – 243 G	(1) राज्य वित्त आयोग
(b) अनु. – 243 H	(2) पंचायत लेखा परीक्षण
(c) अनु. – 243 I	(3) पथ – कर
(d) अनु. – 243 J	(4) सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएँ

कूट :

	a	b	c	d		a	b	c	d
(1)	1	2	3	4	(2)	4	2	3	1
(3)	3	2	4	1	(4)	4	3	1	2

VPM CLASSES

71. ''प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पाठशाला'' कहा जाता है?

(1) भारत (2) अमेरिका

(3) स्विट्जरलैण्ड (4) ब्रिटेन

72. पंचायती राज के किस गोलमेज सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का उद्घाटन किया गया था ?

(1) पहले (2) दूसरे

(3) पांचवें (4) सातवें

73. MNREGA अधिनियम पारित किया गया–

(1) 2005 (2) 2008

(3) 2006 (4) 2009

74. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के अन्तर्गत अपेक्षित निधियों में केन्द्र व राज्य द्वारा वाहित वित्तीय अनुपात है–

(1) 70 : 80 (2) 50 : 60

(3) 75 : 25 (4) 65 : 75

75. कथन (A) : शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरणों की बहुतायत नागरिकों की समस्याओं को बढ़ाती है।
कारण (R) : नए शहरी कार्यों के लिए नए विशेष कार्यकारी निकाय उपयोगी है।

(1) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) गलत है।

(4) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

76. निम्नलिखित में से कौन केन्द्र तथा राज्य सरकारों का वित्त एवं राजस्व का सम्मिलित खाता बनाता है?

(1) लोक लेखा समिति (2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार

(3) योजना आयोग (4) लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

VPM CLASSES

77. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध निर्भर करते हैं–

1. संवैधानिक स्थिति पर
2. संघ सरकार की स्थिरता पर
3. राज्य की राजनैतिक वास्तविकताओं पर
4. व्यक्तिगत समीकरणों पर

नीचे दिए गए कूटों से से सही उत्तर का चयन कीजिए–

कूट :

(1) 1 और 2 केवल
(2) 2 और 3 केवल
(3) 1 ,3 और 4
(4) 2 ,3 और 4

78. 'डैल्फी तकनीक' के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है?

(1) सामूहिक निर्णय
(2) प्रतिबन्धित निर्णय
(3) सत्तात्मक निर्णय
(4) हितैषी (Benevolent) निर्णय

79. निम्नलिखित में से किस एक समिति ने ब्रिटेन के सिविल कर्मचारियों के राजनीतिक क्रियाकलापों पर विचार किया?

(1) नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन समिति
(2) एशटन समिति
(3) मास्टरमैन समिति
(4) प्लोडन समिति

80. निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को ऐसी विषय वस्तु के रूप में वर्णित किया जो एक विधाशाखा बनने की खोज में है और कहा कि यह क्षेत्र किसी भी एकल प्रबल विश्लेषणात्मक प्रतिमान से सर्वथा वंचित है?

(1) एल.डी. व्हाइट
(2) डब्ल्यू. एफ. विलोबी
(3) पॉल एच. एपलबी
(4) ड्वाइट वाल्डो

81. निम्नलिखित मे से किसने 1968 की मिनोब्रुक कॉन्फ्रेन्स की चर्चा चलाई?

(1) एल.डी. व्हाइट
(2) वैमज्ले
(3) ड्वाइट वाल्डो
(4) जॉन रूहर

82. निम्नलिखित में से कौन–सा हर्बर्ट साइमन का कथन नहीं है?

(1) निर्णयों में मूल्य प्रतिज्ञप्तियाँ शामिल नहीं होती
(2) प्रत्येक निर्णय तथ्य एवं मूल्य प्रतिज्ञप्तियों का संयोजन होता है

VPM CLASSES

(3) निर्णयन में सम्पूर्ण तर्कसंगतता संभव नहीं है

(4) निर्णयन अनेक विकल्पों के बीच एक का चुनाव होता है।

83. भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के अन्तर्गत सेवाओं के समूह में रखे गए अनुच्छेद हैं–

(1) अनुच्छेद 310 से 323 तक (2) अनुच्छेद 308 से 323 तक

(3) अनुच्छेद 306 से 323 तक (4) अनुच्छेद 305 से 323 तक

84. निम्नलिखित में से कौन–सा एक निकाय नियमित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण करता है?

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद (2) योजना आयोग

(3) मंत्रिमंडल सचिवालय (4) संघीय मंत्रिमंडल

85. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उस प्रारूप को विहित करने में जिसमें संघ एवं राज्यों की लेखाएं रखी जाएं, अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है–

(1) संसद का

(2) संबधित राज्य के विधानमंडल एवं संसद का

(3) वित्तमंत्री का

(4) भारत के राष्ट्रपति का

86. अशोक मेहता समिति (1977) ने सिफारिश की थी–

(1) मंडल पंचायत की स्थापना की (2) नगर पंचायत की स्थापना की

(3) पंचायत समिति की स्थापना की (4) ग्राम पंचायत की स्थापना की

87. निम्नलिखित में से किस समिति/आयोग ने केन्द्र, राज्य और स्थानीय वित्तों के एकीकरण की सिफारीश की?

(1) कराधान जाँच आयोग (2) स्थानीय वित्त जाँच आयोग

(3) ग्रामीण शहरी संबंध समिति (4) सिंघवी समिति

88. किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की गई?

(1) आंध्रप्रदेश (2) मध्य प्रदेश

(3) राजस्थान (4) गुजरात

VPM CLASSES

89. "लोक प्रशासन एक विज्ञान है" इस दावे को चुनौती दी थी–

(1) फेरेल हेडी ने (2) रॉबर्ट डाल ने

(3) जेम्स जी. मार्च ने (4) सैमुएल हन्टिन्गटन ने

90. एम.पी. फॉलेट के अनुसार, समन्वय का आशय है अवयवों के बीच सुमेल व्यवस्था, क्योंकि समन्वयन–

(1) अप्रत्यक्ष सपंर्क से होता है

(2) किसी परिस्थिति में सभी तत्वों के बीच अन्योन्य संबंध है

(3) कार्यान्वयन के अंतिम चरणों में होता है

(4) एक असंगत प्रक्रिया है।

91. सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है–

(1) विभिन्न मंत्रालयों के बजट आवंटन में वृद्धि के लिए

(2) राजस्व ओर व्यय बजटों के अंतर को भरने के लिए

(3) विशिष्ट मदों पर सरकारी व्यय की वृद्धि के लिए

(4) सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए

92. फ्रैंक गुडनॉ की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में–

(1) विल्सन की मूल विषयवस्तु को और आगे बढ़ाया गया

(2) विल्सन के द्विभाजन का प्रतिवाद किया गया

(3) विल्सन के तर्को को और पुष्ट किया गया

(4) विल्सन के तर्को से सहमत होते हुए नए तर्क प्रस्तुत किये गए।

93. भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके लिए विनियमन जारी करने का अधिकार है?

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(2) लक्षद्वीप

(3) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप दोनों

(4) उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं

VPM CLASSES

94. सूची – I को सूची – II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची – I	**सूची – II**
A. सी. आई. बर्नार्ड	1. 'बाजार–केंटीन' मॉडल
B. डी. ईस्टन	2. 'प्रबंधकीय ग्रिड'
C. एफ. रिग्स	3. तंत्र उपागम
D. ब्लेक एंउ मॉटन	4. आगम–निर्गम मॉडल
	5. 'लिकिंग–पिन' मॉडल

कूट :

	A	B	C	D
(1)	1	2	5	4
(2)	3	4	1	2
(3)	1	4	5	2
(4)	3	2	1	4

95. व्यवहारवादी दृष्टिकोण निर्णयन प्रक्रिया में तीन प्रमुख कारकों को मान्यता देता है। ये हैं–

(1) बौधिक–युक्तिसंगत प्राधिकारी, मान्यताएं एवं प्रभाव

(2) प्रयोजन, स्थान एवं लोग

(3) मान्यताएं, तथ्य एवं नीतियां

(4) लक्ष्य, नीतियाँ एवं आदेश

96. निम्न कथनों पर विचार कीजिए– "निर्णयन के संदर्भ में मानव व्यवहार"–

1. पूर्णरूपेण तर्कसंगत होता है
2. पूर्णरूपेण अतर्कसंगत होता है
3. संतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है
4. असंतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है

उपरोक्त कथनों में से कौन–सा/से कथन सही है/है?

(1) केवल 1 (2) 1 ओर 2 (3) 2 और 4 (4) 3 और 4

VPM CLASSES

97. टेलर एवं फेयॉल की रचनाओं से प्रभावित होकर गुलिक एवं उरविक् ने संगठन के क्लासिकी सिद्धांत को विकसित किया, जो कहलाता है–

(1) पारम्परिक प्रबंधन सिद्धांत
(2) प्रकार्यवादी सिद्धांत
(3) प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत
(4) विभागवाद का सिद्धांत

98. रिग्स के समपार्श्वीय समाज के 'CLECTS' है–

(1) जातीय समूहों के वंशानुगत नेता
(2) मध्यम वर्ग के निर्वाचित नेता
(3) वे नेता जो चुनाव नहीं जीत सके
(4) वे विशिष्ट समूह जो चुनाव जीतने के लिए अपने पारंपरिक प्रभाव का उपयोग करते हैं।

99. निम्नलिखित में से कौन–सा लेखा–परीक्षण के बारे में सत्य कहा है?

(1) यह सिर्फ व्यय पक्ष तक ही सीमित है
(2) भारत में लेखा–परीक्षण केंद्रीय सूची का विषय है
(3) यह खर्च के औचित्य का परीक्षण करता है।
(4) यह कार्य पालिका की ओर से किया जाता है

100. नियमित बजट के पारित होने से पूर्व आगामी वित्त वर्ष के कुछ भाग के लिए अनुमानित व्यय की संसद द्वारा व्यवस्था कहलाती है––

(1) विनियोजन खाता
(2) सांकेतिक कटौती
(3) लेखा अनुदान
(4) कटौती प्रस्ताव

VPM CLASSES

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Answer	3	3	3	2	1	3	1	4	4	1	3	3	4	3	1	4	3	3	4	4
Question	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Answer	2	4	2	3	2	2	4	4	4	2	2	1	2	3	1	1	4	3	4	1
Question	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Answer	3	3	3	1	4	3	4	2	3	4	4	4	1	2	4	2	1	2	4	3
Question	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Answer	1	2	4	3	2	3	4	3	4	4	3	4	1	3	2	4	3	1	3	3
Question	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Answer	2	1	2	1	1	1	3	3	2	2	3	1	3	2	3	4	3	1	4	3

HINTS AND SOLUTIONS

1.(3) प्रक्रिया के आधार पर बनने वाले संगठन कौशल या विशेषीकरण को बताते है।

जैसे :– सिविल इंजीनियरिंग, ये संगठन चूंकि प्रक्रिया पर आधारित होते है, इस कारण इसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण को कम ही महत्त्व या स्वीकृत किया जाता है। ऐसे संगठनों में उच्च तकनीकी क्षमता पायी जाती है। फलस्वरूप लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता न के बराबर ही महसूस होती है।

2.(3) ए. एटजियोनी ने सत्ता को 3 रूपों में विभक्त किया है।

(1) **प्रपीड़क संगठन** – इसमें सत्ता भय के कारण स्वीकार की जाती है।

(2) **उपयोगितावादी संगठन** – प्रतीकात्मक पुरस्कारों के वितरण तथा विवेचन से युक्त इस संगठन में सत्ता निश्चित मानकों पर आधारित होती है।

(3) **आदर्शात्मक संगठन** – यह अनैतिक पुरस्कारों पर आधारित संगठन होता है।

3.(3) भारतीय निर्वाचन आयोग एक नियामकीय अभिकरण है। ऐसे अभिकरणों का मुख्य उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना होता है। ये अभिकरण किसी कार्य या गतिविधि को निष्पक्षता पूर्वक संचालित करने, किसी लोक कानून को क्रियान्वित करने तथा सम्बन्धित कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति से युक्त होते है। भारतीय निर्वाचन आयोग भी इसी श्रेणी का अभिकरण है जो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी होता है।

4.(2) केन्द्रीयकरण व विकेन्द्रीकरण दो विपरीतार्थी अवधारणाएं है। एक ओर नियोजित अर्थव्यवस्था, सशक्त तथा प्रभावशाली प्रतिरक्षा व राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केन्द्रीकरण पर बल देती है। तो वही दूसरी ओर जनसहयोग से लोकतंत्र की स्थापना का आश्वासन व क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती मांग विकेन्द्रीयकरण का समर्थन करती है। आज प्रशासन में भी विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को ही सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है तांकि उत्तरदायित्वों का निष्पादन बेहत्तर ढंग से किया जा सके।

5.(1) अमेरीका में प्रथम हूवर आयोग (1949) ने यह सुझाया था कि भण्डार, स्टेशनरी, सफाई, मरम्मत, मुद्रण तथा प्रतिलिपि इत्यादि ऐसे कार्य है जो सभी संगठनों की, सभी इकाईयों के लिए आवश्यक होते है। अतएव इन कार्यों के लिए एक केन्द्रीयकृत अभिकरण ऐसा होना चाहिए जो केवल इन ग्रहपालक सेवाओं का संचालन करें।

6.(3) 7S मॉडल संगठनात्मक प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसके मुख्य प्रतिपादक एन्थोनी आथोस, रिचर्ड पास्कल, टॉम पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन है।

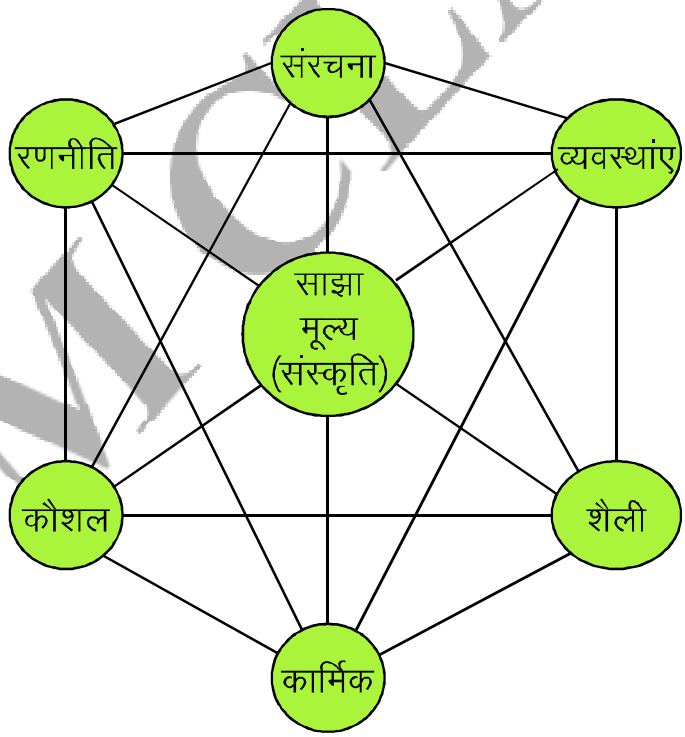

7.(1) यदि किसी संगठन द्वारा किसी विशिष्ट प्रत्यायोजन से किसी बाहरी समिति या निकाय को अल्पकाल के लिए कोई कार्य सौंपा जाता है तो इसे Outward Delegation कहते है। तदर्थ समितियों को ऐसे कार्य दिए जाते है।

VPM CLASSES

8.(4) हैण्डी ने 3I संगठन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। लुइस.ए.एलन ने विकेन्द्रीकरण को व्यावहारिक प्रबंध की कला एवं विज्ञान की प्रशासनिक कार्यविधि में सबसे अधिक उलझाने वाली विधि माना है। डी.हॉक ने 1999 में Chaordic Organization जैसे नवीन संगठन का उल्लेख किया जो वर्तमान में खूब प्रचलित है। शैमरॉक संगठन को तिपत्तियाँ संगठन के रूप में प्रस्तुत करते है।

9.(4) संगठन में समन्वय की स्थापना के लिए न्यूमैन ने पांच पूर्व शर्तें वर्णित की है –

(1) सरलीकृत संगठन

(2) सामजंस्य पूर्ण कार्यक्रम व नीतियां

(3) संचार के सुव्यवस्थित तरीकें

(4) ऐच्छिक समन्वय की सहायता

(5) पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय

10.(1) थियों हैमेन के अनुसार ग्रेकुनाज का अध्ययन अनुभवयुक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है बल्कि शीर्ष प्रबन्धन के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक संगठन की क्या स्थिति होगी, इसका गणितीय प्रस्तुतीकरण है।

11.(3) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मची अफरा–तफरी से उद्योग भी अछूते नहीं रहे। श्रमिकों की अदला–बदली व अनुपस्थिति की दर यकायक बढ़ गयी। तब मेयों द्वारा यह प्रयोग किया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि अनुपस्थितिवाद उस उपक्रम में था जहाँ न तो कोई अनौपचारिक संगठन था और न कोई ऐसा सहज नेतृत्व था जो श्रमिकों को एक समूह के रूप में संगठित कर सके।

12.(3) व्यवहारवादी उपागम की कमियों व आलोचनाओं के कारण जब 1970 के आस–पास उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के परिणामस्वरूप हेण्डरसन ने यह पुस्तक लिखी। जिसमें उत्तर–व्यवहारवादी विचारों, तथ्यों, अभिमतों को समझानें का प्रयास किया गया है।

13.(4) मेरी पार्कर कॉलेट का समग्र चिन्तन मानवतावाद, सहयोग व अपनत्व पर टिका है लेकिन कॉलेट के बहुत से विचार सैदान्तिक तथा आदर्शवादी प्रतीत होते है। कुछ विद्वान् मानते है कि कॉलेट के विचार समय से पहले के विचार है, अतः उन्हें प्रबन्ध में भविष्यवक्ता या पैगम्बर की उपाधि दी जाती है।

VPM CLASSES

14.(3) वारनॉट ने नौकरशाही को पेशेवर विकृत्ति कहा है। विक्टर. ए थॉम्पसन इसे ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा देते है। थॉमसन कार्लाइल नौकरशाही को अव्यावहारिक मानते हुए इसे महाद्वीपीय उत्पात की संज्ञा देते है। डेवी ने इसे व्यावसायिक मनः संताप माना है जो संगठन की दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता है।

15.(1) रेन्सिस लिकर्ट – सामूहिक अभिप्रेरणा

पीटर ड्रकर – उद्देश्यों द्वारा प्रबंध

क्रिस आर्गिरिस – एकीकृत एवं स्वनियंत्रित प्रबंध

हजबर्ग – कार्य समृद्धता

पीटर्स – सशक्तिकरण

16.(4) अत्यांतिक वीटो – सामान्यतः यह वीटो 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है।

(i) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक सम्बंध में

(ii) सरकारी विधेयक के सम्बंध में जब मंत्रिमण्डल त्यागपत्र दे दे।

निलंबनकारी वीटो – राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है।

वॉकेट वीटो – इस मामलों में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है।

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया।

17.(3) सन् 2006 तक लॉर्ड सभा का पदेन अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर कहलाता था, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था, एवं मंत्रिमण्डल का सदस्य माना जाता था। इस व्यवस्था के स्थान पर अब लॉर्ड स्पीकर पद सृजित किया गया है। यह पद आज भी पूर्व की भांति केवल शोभायमान पद है।

VPM CLASSES

18.(3) ब्यूरो
↓
डिविजन
↓
ऑफिस
↓
सर्विसेज
} इनके प्रशासनिक प्रमुख पदसोपानात्मक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

19.(4) फ्रांस में वर्तमान में पंचम गणराज्य प्रवर्तित है। इससे पूर्व चार बार संविधान बन चुका है। वर्तमान संविधान कठोर है। यह लोकतांत्रिक तथा पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। फ्रांस में अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणाली का मिश्रित स्वरूप प्रवर्तित है। इसे अर्द्ध अध्यक्षीय प्रणाली भी कहते हैं।

20.(4) सन् 1951 में राणा के विरूद्ध हुई क्रांति को नियंत्रित करने में भारत की अहम भूमिका रही। फरवरी 1951 में नेपाल नरेश, राणा शासको तथा नेपाली क्रांग्रेस के नेताओं के मध्य एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली सैटलमेण्ट कहा जाता है। समझौते के अनुसार–

1. पूर्ण निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्मित किया जाएगा।
2. अन्तरिम सरकार राणा की अध्यक्षता में सभी पक्षो के प्रतिनिधियों से युक्त होगी।
3. राज्य के हित में नरेश त्रिभुवन को राजा बने रहने दिया जाएगा।

21.(2) वर्तमान में विकास कार्यक्रमों का प्रारूप नियोजित प्रणाली पर तैयार होता है, तथा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना इसका मुख्य ध्येय रहता है। विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट क्षेत्रों की परियोजनाएं निर्मित की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विकासशील राष्ट्रों में परियोजना प्रशासन ही विकास प्रशासन है।

22.(4) अंग्रेजी शब्द Sustain का अर्थ होता है– संभालना या कायम रखना। धारित विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियो की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करता है।

VPM CLASSES

23.(2) डेविड एप्टर ने विकास के समर्थक मूल्यों को उपकरणात्मक तथा बाधक मूल्यों को पूर्णताकारक के रूप में वर्णित किया है। उनके अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूर्णताकारक मूल्य अधिक अभिभावी सिद्ध होते हैं।

24.(3) विकास प्रशासन एक नियामकीय अभिकरण है, जिसमें केन्द्रीयकरण को प्राथमिकता न देकर विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। तांकि कार्य व उत्तरदायित्वों का निष्पादन कुशलता से किया जा सके। इसी कारण विकास प्रशासन विकेन्द्रीकरण की प्रकृति का अनुपालन करता है।

25.(2) विकास प्रशासन तुलनात्मक दृष्टि से नवीन अवधारणा तथा वैचारिक प्रतिमान है, जो नियोजित ढंग से सामाजिक – आर्थिक विकास एवं परिवर्तन के सम्बंध में अध्ययन की विषय वस्तु है। विकास प्रशासन में इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशासनिक तंत्र की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का भाव सम्मिलित रहता है। जो प्रशासनिक विकास को जन्म देता है।

26.(2) प्रधानमंत्री
↓
केबिनेट मंत्री
↓
राज्य मंत्री
↓
उपमंत्री
↓
संसदीय सचिव
↓
अतिरिक्त / संयुक्त सचिव
↓
उप सचिव / निदेशक
↓
अवर सचिव
↓
अनुभाग अधिकारी

27.(4) डेस्क ऑफिसर सिस्टम की शुरूआत ब्रिटिश व्हाईट हॉल परम्परा पर 1950 से कुछ मंत्रालयों में चालू की गई। डेस्क ऑफिसर पद अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रणाली में कम महत्व के मामले स्वयं डेस्क ऑफिसर ही निपटाता है। जबकि

VPM CLASSES

नीतिगत मामले ही उपसचिव या उससे उच्च अधिकारियों तक भेजे जाते हैं।

28.(4) योजना आयोग की स्थापना के समय छः संभाग थे। कालांतर में आयोग का कार्यक्षेत्र व योजनाओ का स्वरूप विस्तृत होने पर संभागो व अन्य प्रशासनिक इकाईयों में स्वाभाविक वृद्धि हुई। सन् 2007 में योजना आयोग द्वारा निर्मित स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बंधी राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन आयोग का स्वैच्छिक संगठन प्रकोष्ठ करता है।

29.(4) सन् 1961 में गठित C.S.O. सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का प्रमुख स्वायत्तशासी निकाय है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (P.E.O.) की स्थापना 12 अगस्त, 1952 को की गई थी। यह संगठन योजनाओं के प्रबोधन, सर्वेक्षण, निष्पादन, उद्देश्य की सीमा का अध्ययन करता है। NSSO की स्थापना सन् 1950 में की गई थी। सन् 2007 में एक सोसायटी के रूप में गठित जनसंख्या स्थिरता कोष योजना आयोग के निर्देशन में कार्य करता है।

30.(2) कार्यविधि नियमों के अनुसार मंत्रिमण्डल सचिव ही प्रशासनिक स्तर का शीर्षस्थ कहलाता है। किन्तु वह प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है, के अधीन ही कार्य करता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्टतम लोक सेवक होने के कारण देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद धारण करता है। यह प्रधानमंत्री को आंख व कान की भांति हर सम्भव प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

31.(2) D.P.C. से तात्पर्य है, विभागीय पदोन्नति समिति। इस समिति में प्रायः 3–4 अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जो सेवा अभिलेख, साक्षात्कार, तथा अन्य आधारों पर कार्मिक की योग्यता का आकलन करते है। इस पद्धति में चापलूसी व भाई–भतीजावाद को प्रत्यक्ष मिलता है।

32.(1) भारत की लोक सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च स्थान है। इन सेवाओं के अधिकारी केन्द्र या राज्य कहीं भी आवश्यकतानुसार पदस्थापित किये जा सकते हैं। किंतु फिर भी अखिल भारतीय सेवाओं ने राज्य की स्वायत्तता को एक सीमा तक भंग करने का प्रयास किया है, क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारी केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन होते हैं, तथा राज्य सरकार द्वारा उन पर पूर्ण नियंत्रण रख पाना सम्भव नहीं होता।

33.(2) कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1996 में जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत लोक नीति में सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य प्रशिक्षण प्रसार, प्रबंधन व सूचना के अधिकार प्रशिक्षण संचालित होते है। ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा I.A.S. के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार

VPM CLASSES

का प्रमुख मंत्रालय है।

34.(3) संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च केन्द्रीय भर्ती अभिकरण है। U.P.S.C. ने अपनी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रारूप के द्वारा नई आवेदन प्रणाली सन् 1999 से शुरू की है, जो एक समायोजित सुधार कहा जा सकता है, क्योंकि U.P.S.C. को प्रतिवर्ष 10–11 लाख आवेदन पत्रों की छंटनी करनी पड़ती है। यह प्रणाली Project SAMPERA के अन्तर्गत विकसित की गई है।

35.(1) (I.E.S.) भारतीय आर्थिक सेवा समूह ''क'' की केन्द्रीय सेवाओं में सबसे नई सेवाओं में से है। जिसका गठन 1961 में हुआ। इस सेवा का गठन आर्थिक नीति के निरूपण व कार्यान्वयन के क्षेत्र में विशेष संवर्ग होने की महसूस की गई जरूरत के आधार पर किया गया है।

36.(1) 1. पूर्व अंकेक्षण किसी कार्य के लिए धन की उपलब्धता तथा व्यय की वैधता की जानकारी के लिए किया जाता है।

2. पश्चात् अंकेक्षण व्यय हो जाने के पश्चात् उसके लेखो तथा दस्तावेजो का पोस्टमार्टम होता है।

3. प्रशासनिक अंकेक्षण तकनीक, कार्मिक तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं की जांच के लिए किया जाता है।

4. वित्तीय अंकेक्षण धन की प्राप्ति, रख–रखाव, व्यय तथा उसके कुशल प्रबंधन से सम्बंधित होता है।

37.(4) भारत में 1975 से एकीकृत वित्तीय सलाहकार व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस सलाहकार का चयन सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय व वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व बजट निर्माण, व्यय नियंत्रण, भुगतान, लेखा एकत्रण, विनियोग लेखा निर्माण, आन्तरिक अंकेक्षण तथा वित्तीय अनुशासन स्थापित करना इत्यादि है।

38.(3) भारतीय लोक लेखा संगठन के सभी अधिकारी लेखा नियंत्रक के निर्देशन–नियंत्रण में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या संगठनों में पदस्थापित होते हैं। इन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 1992 से नई दिल्ली में शासकीय लेखा व वित्त संस्थान कार्यरत है।

39.(4) किसी विधेयक को धन विधेयक समझे जाने के लिए भारत के लोक लेखो को मध्यनजर रखते हुए धन प्राप्ति की इच्छा, भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा व किसी कर में

VPM CLASSES

कटौती या परिवर्तन जैसी मुख्य अर्हताएं धन विधेयक की मान्यता प्रदान करती है।

40.(1) आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त रक्त की भूमिका निर्वाहित करता है। यद्यपि प्रशासन व वित्त दो पृथक्- पृथक् संकल्पनाएं है, जिसमें प्रशासन सेवा व सरकार तथा वित्त आय–व्यय समालेखों का रूप होता है। कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के निर्देशन व अनुमति द्वारा बजट का क्रियान्वयन किया जाता है।

41.(3) संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के लिए 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वे ऐसा करने के लिए बाध्य है। इसके अनुसार प्रतिवर्ष राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के वित्त आयोग के नियमानुसार होता है, न कि राज्य वित्त आयोग के।

42.(3) भारत के संविधान में जिला शब्द अनु. 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में प्रयुक्त हुआ है। अनु. 243 में पंचायती राज के लिए जिला परिषद् हेतु व छठी अनुसूची में कुल राज्यों में स्वशासी जिलों हेतु प्रयुक्त हुआ है।

43.(3) छोटा नेपोलियन शब्द जिला कलक्टर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि पूर्व में कलक्टर को इसी नाम से जाना जाता था। किंतु अब जिला कलक्टर अपनी परम्परागत भूमिका को त्याग कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित है।

44.(1) 13वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर 2007 में किया गया था। इस आयोग के विचारार्थ कई विषय थे, किंतु उनमें प्रमुख विषय कार्य था– राज्यों में पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की संचित निधि के आवर्धन हेतु आवश्यक उपाय/सुझाना।

45.(4) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए नगरीय निर्धनता का (उन्मुलन) उपशमन करना, आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु योजनाएं बनाना तथा चर्मशोधनशालाओं का विनियमन करना, नगरीय वानिकी को प्रोत्साहित करने जैसे कार्यों का उल्लेख किया गया है।

46.(3) परिकल्पना प्रत्यात्मक तत्वों के सम्बंध में एक अवधारणा मात्र होती है। यह एक अनुमानित

VPM CLASSES

समाधान है। इसमें कथन को अस्थायी रूप में सही मानकर इसकी पुष्टि का प्रयास किया जाता है। किसी शोध प्रक्रिया के नियोजन के लिए यह दिशा या आधार प्रदान करती है।

47.(4) योजना तंत्र से सम्बंधित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन एक नियामकीय अभिकरण है, जो कार्यों का निष्पादन व मूल्यांकन करता है। P.E.O. इस हेतु मूल्यांकनात्मक शोध पद्धति का अनुसरण करता है जो कार्यों के निष्पादन के पश्चात् की जाती है।

48.(2) विभेदी प्रवणता परीक्षण जिसे DAT कहते हैं। एक अत्यधिक प्रसिद्ध व बहुतायत से प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण है। इसमें प्रशासन को कुल 90 मिनट का समय दिया जाता है।

49.(3) SEM = मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि

σ = जनसंख्या का प्रमाणिक विचलन

N = न्यादर्श का आकार

न्यादर्श का जितना बड़ा आकार होता है, प्रमाणिक ऋुटि उतनी ही कम होती है, अन्य सांख्यिकीयों की विश्वसनीयता उनकी प्रमाणिक त्रुटि से ज्ञात की जाती है।

50.(4) सामाजिक शोध में उपकरणों की प्रमाणिकता के अभाव के कारण निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं होते हैं। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में मुख्य सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जिनके लिए मापनियां उपलब्ध नहीं हो पाती। सामाजिक विषय में कई प्रत्यय व अवधारणाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती। ऐसे तथ्यों से प्राप्त प्रदत्तों की अविश्वसनीयता के कारण शोधकर्त्ता सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं कर पाता।

51.(4) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 10–20 होनी चाहिए। समूह को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए, जिसमें सदस्यों को विचारों के आदान–प्रदान व सहभागिता की छूट हो। समूह को अपने सुगम संचालन के लिए एक आचार–संहिता बनानी चाहिए।

52.(4) सामाजिक परिवर्तन हेतु जहां तक बाहरी कारकों का प्रश्न है। उनमें सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन, नगरीकरण औद्योगिकीकरण, देशान्तरगमन, आक्रमण, युद्ध, प्रभुता, व्यापार, संचार के साधन, सामाजिक दशाएं, भौतिक हालात जैसे सूखा, बाढ़, भूकम्प में परिवर्तन प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

53.(1) 69वां संशोधन अधि. 1991 में केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए

VPM CLASSES

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। 75वें संशोधन अधि. में किराया न्यायालयों की स्थापना जो किराया विवादों को सुलझाए। यह न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक व किराएदार के हितों के संबंध में नियामक एवं नियंत्रण स्थापित करेंगे। 80वें संविधान संशोधन अधि. 2000 केन्द्र व राज्य के मध्य राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। 83वां संविधान संशोधन अधि. 2000 अरूणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचि जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है।

54.(2) विलियम जेनकिन्स के अनुसार लोक नीति किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्णयों का परिष्कृत रूप होती है। जिसका सम्बंध लक्ष्यों के चयन व उन लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने हेतु अपनाए जाने वाले साधनों से होता है। वहां सैदान्तिक रूप से ऐसे निर्णयों को क्रियान्वित करने का अधिकार उन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की सत्ता की सीमा में ही होता है।

55.(4) सारगत नीतियां समाज कल्याण के उद्देश्य से सम्बंधित होती है। यही कारण है कि सरकार शिक्षा का प्रबंध लोककल्याण को ध्यान में रखकर ही करती है। वितरक नीतियां समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है, जो पिछड़े व अशक्त वर्ग के होते हैं। उनके लिए सरकार पोषाहार कार्यक्रमों का संचालन करती है। नियंत्रक नीतियां व्यापार, व्यवसाय व सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनायी जाती है। राज्य परिवहन निगम का निर्माण भी प्रशासन द्वारा नागरिकों की पथ परिवहन सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। पूंजीकरण नीतियों के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों को संघीय सरकार द्वारा वित्तीय राहत प्रदान की जाती है।

56.(2) योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होते हुए भी भारत के सम्पूर्ण आयोजना तंत्र का प्रमुख केन्द्रबिंदु बन चुका है। एक मंत्रणा अभिकरण के रूप में स्थापित हुआ योजना आयोग सूत्र अभिकरण बनता जा रहा है। योजना का प्रारूप या मसौदा एक बार जैसा योजना आयोग स्वीकृत कर देता है, वह न्यूनाधिक मात्रा में अंत तक उसी रूप में स्वीकृत हो जाता है।

57.(1) सामाजिक कार्यों का निर्धारण सामाजिक परिवर्तन का मुख्य अंग है। क्योंकि इन कार्यों से ही एक सभ्य समाज का जन्म होता है। जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के साथ–साथ प्रशासनिक मानक व मूल्यों का भी समावेश होता है। ऐसे समाजों में प्रशाासन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से जो कार्य करता है, वे उसे समाज द्वारा स्वतः वैधानिकता प्रदान करते हैं।

58.(2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अल्पावास ग्रह योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत उन महिलाओं व बालिकाओं को अस्थायी आश्रय, परामर्श, मनश्चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती है। जो मानसिक असंतुलन, भावनात्मक अशांती व सामाजिक उत्पीड़न की शिकार हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं का पुनर्वास करना व उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

59.(4) TRYFED का पूरा नाम भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ है। यह जनजातियों लोगों को शोषण से बचाने तथा उन्हें छिटपुट वन उत्पादों व अपनी जरूरत से अधिक कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में इसका गठन किया।

60.(3) भारत सरकार द्वारा 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव पर 1953 ई. में UGC की स्थापना की गई। 1956 में संसद के अधि. के द्वारा इसे वैधानिक संस्था स्वीकार कर लिया गया। इस अधि. के अनुसार चैयरमेन तथा सचिव के अतिरिक्त UGC के 9 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य शिक्षा स्तर को उच्च बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देना है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन सीधे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है।

61.(1) सन् 1964 में हुए श्रीमान भण्डारनायके तथा लाल बहादुर शास्त्री समझौते के अन्तर्गत श्रीलंकाई शरणार्थियों का केरल में पुनर्वास करने हेतु मई 1970 में इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार (40%) तथा केरल सरकार (60%) की संयुक्त पूंजी से बनी यह सार्वजनिक कम्पनी सरकारी स्तर पर रबर के पौधे लगाती है।

62.(2) लोक निगम अपने दैनन्दिन कार्यों में संसदीय तथा मंत्री के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। इनके निदेशक मण्डलो के सदस्यो के चयन में सरकार की भूमिका निर्णायक रहती है। ये निगम जनसेवा के उद्देश्य हेतु प्रयासशील होते हैं। संसद में इनके सम्बंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, बहस हो सकती है तथा संसदीय लोक उपक्रम समिति नियंत्रण करती है, लेकिन संसद दैनन्दिन प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसी कारण W.A. रॉब्सन ने लोक निगमों को बीसवीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक नवीनता या मौलिकता कहा है।

VPM CLASSES

63.(4) सरकार ने वर्ष 1997 में नवरत्न योजना प्रारंभ की थी। जिससे तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले उद्यमों की पहचान की जा सके तथा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य धारण कर पाने में उनकी सहायता की जा सके। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 20 नवरत्न उद्यम है।

64.(3) प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा (7) के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से 14 अक्टूबर 2003 से भारतीय प्रतियोगिता आयोग की स्थापना की थी। यह आयोग परामर्शकारी व क्षमतावर्धनों कार्यक्रमों तक ही सीमित है। आयोग ने प्रतियोगिता परामर्श, जनता की जागरूकता तथा प्रशिक्षण से सम्बंधित गहन कार्य किया है।

65.(2) उदारीकरण व निजीकरण के युग में भारतीय लोक सेवा भी अछूती नहीं रही है। उदारीकरण व निजीकरण ने लोक सेवा को नवीनतम प्रबंधकीय रूप प्रदान किया है। यही कारण है कि आज लोक सेवाओं में उच्च व योग्यतम कार्मिकों की भर्ती की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। उच्च प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु नये–नये प्रशासनिक – व्यावसायिक नियम बनाए जा रहे हैं।

66.(3) 74वें संविधान संशोधन अधि. के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में त्रि–स्तरीय नगरीय स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है। जिनमें से एक नगर परिषद् भी है। यह व्यवस्था उन छोटे–छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए की जाती है, जिनमें 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है।

67.(4) छावनी बोर्ड एक निगमित निकाय है। इन पर केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय का सीधा नियंत्रण होता है। केन्द्र का समादेश अधिकारी छावनी मण्डल का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

68.(3) बम्बई महानगरीय प्रादेशिक आयोजन परिषद् एक सांविधिक निकाय है। इसकी रचना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर आयोजन अधि. 1966 के अनुसार 1967 में की गयी थी। इसका मुख्य कार्य सैनिक व प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों हेतु अधिग्रहित क्षेत्रों का परिरक्षण, वनारोपण, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना आदि है।

69.(4) 16 जुलाई, 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया, जिसने 3 f प्रतिमान सुझाया–

F – फंक्शन (कार्य)

F – फण्ड (निधि)

F – फंक्शनरीज (कार्मिक)

70.(4) 73 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अनु. – 243 (G/छ) में इन संस्थाओं को सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने व लागू करने का प्रावधान किया गया है। अनु. – 243 (H/ज) द्वारा इन्हें कर, शुल्क, पथकर तथा फीस एकत्र करने की शक्तियां दी गई है। अनु. – 243 (I/झ) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 3 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अनु. – 243 (J/ञ) पंचायतों के लेखाओं के परीक्षण सम्बंधी प्रावधान करता है।

71.(3) स्विट्जरलैण्ड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। यहां राज्यों (कैण्टन) के अधीन स्थानीय स्तर पर कम्यून नामक संस्था होती है। यहां शासन के प्रत्येक स्तर को विकेन्द्रित आधार पर ही गठित किया जाता है।

72.(4) दिसम्बर 2004 में जयपुर में आयोजित हुए सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। यह पोर्टल पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ती है।

73.(1) MNREGA का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम है। जो 2005 में पारित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को प्रति परिवार एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार सरकार द्वारा S.K.M. की परिधि में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

74.(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके अन्तर्गत अपेक्षित निधियों को 75 : 25 के अनुपात में केन्द्र व राज्यों के बीच वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधे रूप से निधियां जारी की जाती है।

75.(2) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण होते हैं, जो भिन्न–भिन्न क्षेत्रों जैसे परिवहन, जलापूर्ति, क्षेत्रीय विकास, शहरीकरण उन्मूलन, गंदी बस्ती निवारण इत्यादि से सम्बंधित होते है। किंतु नागरिकों को फिर भी इनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। उनकी समस्याएं समय

VPM CLASSES

पर इन प्राधिकरणों के कारण हल होने की बजाए बढ़ती जाती है, क्योंकि ये प्राधिकरण जटिल औपचारिक नियमों में बंधे होते हैं।

किंतु यदि नए कार्यकारी निकायो को इस हेतु गठित कर प्रोत्साहित किया जाए उन्हें जन समस्याओं के कारणों का जानने व समझने का अवसर दिया जाए तो प्राधिकरण सफल व सहयोगी हो सकते हैं।

76.(4) लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग केन्द्र तथा राज्य सरकारों का वित्त एवं राजस्व का सम्मिलित खाता बनाता है।

77.(3) राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध संवैधानिक स्थिति पर,राज्य की राजनैतिक वास्तविकताओं पर एंव व्यक्तिगत समीकरणों पर निर्भर करते है।

78.(1) सामूहिक निर्णय , 'डैल्फी तकनीक' के बारे में सही है।

79.(3) मास्टरमैन समिति ने ब्रिटेन के सिविल कर्मचारियों के राजनीतिक क्रियाकलापों पर विचार किया।

80.(3) पॉल एच. एपलबी ने लोक प्रशासन को ऐसी विषय वस्तु के रूप में वर्णित किया जो एक विधाशाखा बनने की खोज में है और कहा कि यह क्षेत्र किसी भी एकल प्रबल विश्लेषणात्मक प्रतिमान से सर्वथा वंचित है।

81.(2) वैमज्ले ने 1968 की मिनोब्रुक कॉन्फ्रेन्स की चर्चा चलाई।

82.(1) निर्णयों में मूल्य प्रतिज्ञप्तियाँ शामिल नहीं होती।

83.(2) भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के अन्तर्गत सेवाओं के समूह में रखे गए अनुच्छेद अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं।

84.(1) राष्ट्रीय विकास परिषद नियमित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण करता है।

85.(1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उस प्रारूप को विहित करने में जिसमें संघ एवं राज्यों की लेखाएं रखी जाएं, संसद का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

86.(1) अशोक मेहता समिति (1977) ने मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी।

87.(3) ग्रामीण शहरी संबंध समिति ने केन्द्र, राज्य और स्थानीय वित्तों के एकीकरण की सिफारीश की।

88.(3) राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की गई।

89.(2) "लोक प्रशासन एक विज्ञान है" रॉबर्ट डाल ने इस दावे को चुनौती दी थी।

VPM CLASSES

90.(2) एम.पी. फॉलेट के अनुसार, समन्वय का आशय है अवयवों के बीच सुमेल व्यवस्था, क्योंकि समन्वयन किसी परिस्थिति में सभी तत्वों के बीच अन्योन्य संबंध है।

91.(3) विशिष्ट मदों पर सरकारी व्यय की वृद्धि के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है।

92.(1) फ्रैंक गुडनॉ की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में विल्सन की मूल विषयवस्तु को और आगे बढ़ाया गया।

93.(3) भारत के राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप दोनों के लिए विनियमन जारी करने का अधिकार है।

94.(2)

सी. आई. बर्नार्ड	-	तंत्र उपागम
डी. ईस्टन	-	आगम–निर्गम मॉडल
एफ. रिग्स	-	'बाजार–कैंटीन' मॉडल
ब्लेक एंउ मॉटन	-	'प्रबंधकीय ग्रिड'

95.(3) व्यवहारवादी दृष्टिकोण निर्णयन प्रक्रिया में तीन प्रमुख कारकों को मान्यता देता है। ये प्रमुख कारक मान्यताएं, तथ्य एवं नीतियां है।

96.(4) "निर्णयन के संदर्भ में मानव व्यवहार" –

1. संतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है।
2. असंतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है।

97.(3) टेलर एवं फेयॉल की रचनाओं से प्रभावित होकर गुलिक एवं उरविक् ने संगठन के क्लासिकी सिद्धांत को विकसित किया, जो प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत कहलाता है।

98.(1) रिग्स के समपार्श्वीय समाज के 'CLECTS' जातीय समूहों के वंशानुगत नेता है।

99.(4) लेखा–परीक्षण कार्य पालिका की ओर से किया जाता है।

100.(3) नियमित बजट के पारित होने से पूर्व आगामी वित्त वर्ष के कुछ भाग के लिए अनुमानित व्यय की संसद द्वारा व्यवस्था लेखा अनुदान कहलाती है।

VPM CLASSES